[श्री कृष्ण प्रताप सिंह]

द्वारा उद्घाटन किया गया था और इसे 4 अक्तूबर को चालू किया जाना था । संयंत्र के इंजीनियरों के अनुसार इसमें इलेक्ट्रो-मेगनेटिक बाइब्रा फीडर के डिजाइन में गम्भीर दोष पाए गए हैं । ये बम्बई की एक निजी फर्म द्वारा सप्लाई किए गए थे । इसकी डिजाइन क्षमता 300 टन कोयला प्रति घंटे ढोने की निर्धारित की गई थी, किन्तु यह 20 टन से अधिक नहीं ढो सकते हैं ।

माननीय इस्पात मंत्री से निवेदन है कि इस बारे में एक वक्तव्य देने की कृपा करें ।

(iv) ADEQUATE COMPENSATION TO LAND OWNERS FOR THEIR ACQUIRED LAND IN UTTAR PRADESH

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, हमारे देश के किसानों की भूमि का अर्जन लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत हो रहा है । यह 88 वर्ष पुराना कानून है । अंग्रेजी सरकार का बनाया हुआ है । भूमि का मूल्य इस ऐक्ट की धारा 4 की अधिसूचना के समय का दिया जाता है । किसानों की जब भूमि ली जाती है तो उससे अनेक वर्ष पहले का भाव होता है । जब भूमि पर अधिकार किया जाता है उस समय के सूल्य से 10 प्रतिशत से लेकर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होता । सरकार ने इस ऐक्ट में संशोधन का बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया है । उसमें भी बहुत कमी है । उत्तर प्रदेश सरकार अपने आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 व 6 की अधिसूचना और घोषणा में तीन वर्ष से अधिक का अन्तर न होने के प्रतिबन्ध की अवेहलना अपने अधिनियम की धारा 55 के अनुसार भी करके मथुरा जिले में भूमि ले रही है । भारत सरकार से प्रार्थना है कि वह बिल पर शीघ्र विचार करे । संसत्सदस्यों के सुझावों के अनुसार संशोधन अपने बिल में करे और शीघ्र पास करके किसानों के साथ अन्याय को रोके और उत्तर प्रदेश सरकार को भी कानून के खिलाफ कार्यवाही न करने का सुझाव दे ।

(v) PLIGHT OF BONDED LABOUR IN THE COUNTRY

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram): I would like to draw the immediate attention of the House, and thereby the Union Government, about the serious plight of the bonded labourers in our country, with special reference to the recent incidents of harassment and torture of the bonded labourers from Tamil Nadu in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, under the tyranny of the contractors.

As per the reports of the Ministry of Labour, 1,44,930 bonded labourers have been identified, of which 84,269 only have been rehabilitated throughout the country, as on 30-6-1982. But in a survey of National Labour Institute, the number of bonded labourers is as high as 2.3 million. The National Labour Institute surveyed 572 villages of 42 districts, and identified 5,00,000 bonded labourers. Actually, the figure may be manifold, as almost all the bonded labourers are ignorant, and are under the constant threat and horror of the contractors, leading to failure of disclosure of their identity as bonded labourers.

With reference to the bonded labourers from Tamil Nadu at Raison and Vidisha in Madhya Pradesh, the poor labourers were lured by job opportunities by agencies of the contractors, with